माननीय न्यायमूर्तिगण आर.एन.मित्तल एवं एम.एम. पुंछी के समक्ष

सोहन लाल,-याचिकाकर्ता।

बनाम

श्रीमती. -कमलेश, प्रतिवादी।

1983 का सिविल संशोधन क्रमांक 2154

6 फ़रवरी 1984

हिंदू विवाह अधिनियम (1955 का XXV) - धारा 9 और 24 - दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका में लंबित मुकदमे के भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च के लिए प्रतिवादी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत करना - पुनर्स्थापन के लिए याचिका वापस ली गई के रूप में खारिज कर दी गई - का आवेदन प्रतिवादी - क्या मुख्य याचिका के निपटारे के बाद जारी रह सकता है - धारा 24 के तहत एक आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका - क्या मुख्य कार्यवाही के निपटारे के बाद जीवित रहता है - भरण-पोषण पेंडेंट लाइट और व्यय - क्या फैसले की तारीख तक दिया जाना है मुख्य कार्यवाही का निस्तारण.

यह माना गया कि अदालत हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, अर्थात् दाम्पत्य अधिकारों की बहाली, न्यायिक अलगाव, तलाक या विवाह की शून्यता के लिए,

ऐसे पति या पत्नी को अनुदान जिसके पास अपना भरण-पोषण करने और कार्यवाही, मुख्य-किरायेदारी पेंडेंट लाइट और मुकदमेबाजी के आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं है। धारा 24 को अधिनियमित करने का उद्देश्य यह है कि एक निर्धन पति या पत्नी को अपनी गरीबी के कारण कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसे आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय करे ताकि निर्धन पति या पत्नी धन की कमी के कारण विकलांग न हो। हालाँकि, यदि धारा 24 के तहत आवेदन पर मुख्य याचिका के लंबित रहने के दौरान दूसरे पति या पत्नी की टालमटोल की रणनीति के कारण या कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण निर्णय नहीं लिया जाता है, तो धारा 24 के तहत आवेदन को इस आधार पर खारिज करने की स्थिति में धारा का पूरा उद्देश्य विफल हो जाता है। मुख्य याचिका के निर्णय के बाद यह टिक नहीं पाता। इसलिए, भले ही मुख्य याचिका पर अंतिम निर्णय हो जाए, धारा 24 के तहत आवेदन जिस पर निर्णय लंबित है, जारी रह सकता है। इसी तरह, धारा 24 के तहत किसी आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका मुख्य याचिका के निपटारे के बावजूद जारी रह सकती है।

(पैरा 5)

निर्मला बनाम राम दास, ए.आई.आर. 1973 पंजाब एवं हरियाणा 48,

सावित्री पिपलानी बनाम सुभाष चंदर, सी.आर. 114, 1979 का निर्णय हुआ

15 नवंबर 1979.

सावित्री पिपलानी बनाम सुभाष चंदर, सीआर 244 ऑफ़ 1980, 21 नवंबर 1980 [1982 मैरिज लॉ जर्नल 108 (पीबी)]

अति-शासित।

चित्रा लेखा बनाम रंजीत राय, ए.आई.आर. 1977 दिल्ली 176.

रीता मागो बनाम वी. पी. मागो, 1982 हिंदू लॉ रिपोर्टर, 201 (दिल्ली)।

से असहमत।

माना गया कि धारा 24 में 'कार्यवाही' शब्द तीन स्थानों पर आता है और यह मुख्य कार्यवाही को दर्शाता है, यानी धारा 24 के तहत कार्यवाही के अलावा अन्य कार्यवाही। 'कार्यवाही के दौरान मासिक ऐसी राशि' शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये शब्द विधायिका की मंशा को दर्शाते हैं कि वह मुख्य याचिका के निपटारे तक निर्धन पति या पत्नी को गुजारा भत्ता देने का इरादा रखती है। यदि धारा 24 के तहत आवेदन को 'कार्यवाही' शब्द में शामिल किया जाता है, तो अजीब परिणाम सामने आएंगे। इसलिए, यदि धारा 24 के तहत आवेदन मुख्य याचिका के खारिज होने के बाद भी जारी रहता है, तो आवेदक मुख्य याचिका के निर्णय की तारीख तक भरण-पोषण का हकदार है।

(पैरा 11).

खुराना बनाम श्रीमती. दीपक, ए.आई.आर. 1981 पंजाब और केवल इसी सीमा तक शासन किया गया।

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री के.एस. भुल्लर, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के न्यायालय के 30 जुलाई, 1983 के आदेश में संशोधन के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत समीक्षा और आवेदन को बहाल करने के लिए आवेदन को मिश्रित किया गया।

याचिकाकर्ता के वकील के.के. कुकप्रिया।

प्रतिवादी की ओर से हेमन्त गुप्ता, अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र नाथ मित्तल

,(1) यह अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के आदेश के खिलाफ निर्देशित एक पुनरीक्षण याचिका है।

(2) संक्षेप में, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता सोहन लाल ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए अपनी पत्नी के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम (इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की। प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 24 के तहत भरण-पोषण लंबित मुकदमे और मुकदमेबाजी खर्च के अनुदान के लिए एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायाधीश ने उसे आदेश सुनाने के लिए स्थगित कर दिया. आदेश की घोषणा से पहले पति ने धारा 9 के तहत याचिका वापस ले ली और परिणामस्वरूप इसे वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने याचिका खारिज होने के मद्देनजर धारा 24 के तहत आवेदन को निरर्थक मानते हुए खारिज कर दिया। पत्नी ने धारा 24 के तहत आवेदन पर पारित आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि धारा 9 के तहत याचिका खारिज होने के मद्देनजर, धारा 24 के तहत आवेदन निष्फल नहीं हुआ।

(3) समीक्षा आवेदन का पति ने विरोध किया, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ दलील दी कि उसकी पत्नी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत रखरखाव के लिए अलग-अलग कार्यवाही दायर की थी, और आवेदन गलत था। उन्होंने यह भी दलील दी कि धारा 9 के तहत याचिका खारिज होने के बाद, धारा 24 के तहत आवेदन टिक नहीं सकता।

(4) विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने बर्खास्तगी के आदेश की समीक्षा की और अधिनियम की धारा 24 के तहत आवेदन को बहाल कर दिया। 'पति उक्त आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आया था। प्रस्ताव की सुनवाई के समय, विद्वान न्यायाधीश ने पाया

इस न्यायालय के निर्णयों में विरोधाभास। नतीजतन, पुनरीक्षण याचिका डिवीजन बेंच में स्वीकार कर ली गई, मामला इस प्रकार हमारे सामने है,

(5) निर्धारण के लिए पहला प्रश्न यह उठता है कि यदि अधिनियम के तहत मुख्य याचिका पर अंतिम निर्णय हो जाता है, तो क्या अधिनियम की धारा 24 के तहत भरण-पोषण लंबित मुकदमे और मुकदमेबाजी खर्च के लिए आवेदन, जिस पर निर्णय लंबित है, जारी रखा जा

सकता है . धारा 24 लंबित मुकदमे के भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चों से संबंधित है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

"जहां इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में, अदालत को यह प्रतीत होता है कि पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, के पास उसके समर्थन और कार्यवाही के आवश्यक खर्चों के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, तो वह, पत्नी या पति के आवेदन पर, प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को कार्यवाही के खर्च का भुगतान करने का आदेश दें, और कार्यवाही के दौरान मासिक रूप से ऐसी राशि का भुगतान करें, याचिकाकर्ता की अपनी आय और प्रतिवादी की आय को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय को उचित प्रतीत हो सकता है।"

धारा को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि न्यायालय, अधिनियम के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, जैसे कि दाम्पत्य अधिकारों की बहाली, न्यायिक अलगाव, तलाक या विवाह की शून्यता के लिए, पर्याप्त धन न होने पर पति या पत्नी को अनुमति दे सकता है। स्वयं के भरण-पोषण के लिए और कार्यवाही, लंबित मुकदमे के रखरखाव और मुकदमेबाजी के आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए आय। इस धारा को अधिनियमित करने का उद्देश्य यह है कि किसी निर्धन पति/पत्नी को कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अपनी गरीबी के कारण कष्ट न सहना पड़े। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसे आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय ले ताकि धन की कमी के कारण निर्धन पति या पत्नी विकलांग न हो। हालाँकि, यदि धारा 24 के तहत आवेदन पर मुख्य याचिका के लंबित रहने के दौरान दूसरे पति या पत्नी की टालमटोल की रणनीति के कारण या कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण निर्णय नहीं लिया जाता है, तो खारिज होने की स्थिति में धारा का पूरा उद्देश्य समाप्त हो जाता है। इस आधार पर कि मुख्य याचिका के निर्णय के बाद इसका अस्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए, हमारा विचार है कि भले ही मुख्य याचिका पर अंतिम निर्णय हो जाए, धारा 24 के तहत आवेदन, जिस पर निर्णय लंबित है, जारी रह सकता है। इसी प्रकार, धारा 24 के तहत किसी आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका निस्तारण के बावजूद जारी रह सकती है? मई^ याचिका. उपरोक्त दृष्टिकोण में, हम अमरीक सिंह बनाम श्रीमती मामले में डी.एस. तेवतिया, जे. की निम्नलिखित टिप्पणियों से मजबूत हुए हैं। नरिंदर कौर (1):-

"यदि विचार यह है कि अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों का उद्देश्य विधायिका द्वारा निर्धन पति या पत्नी को अपने खिलाफ कार्यवाही का बचाव करने और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान खुद को बनाए रखने के लिए साधन सुरक्षित करने में सक्षम बनाना था, तो यह उस पर निर्भर है अदालतों को अधिनियम की धारा 24 के तहत याचिका पर तत्काल निर्णय लेना होगा, अन्यथा देरी से उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अन्यथा ऐसे मामले में जहां अदालत मुख्य मामले की सुनवाई के अंत तक आवेदन पर निर्णय लेने में देरी करती है,

आवेदक को भरण-पोषण और मुकदमेबाजी के खर्च के अधिकार से इस विशेष तर्क पर वंचित कर दिया जाएगा कि वह मुकदमा चलाने में सक्षम थी। इतनी लंबी अवधि तक मुकदमेबाजी की और जीवित रही और इसलिए वह अपने आवेदन पर अनुकूल आदेश पाने की हकदार नहीं थी, मुकदमेबाजी के खर्चों के लिए और अधिनियम की धारा 24 के तहत अंतरिम रखरखाव का उद्देश्य केवल एक गरीब पति या पत्नी की आकस्मिकता को पूरा करना था जो सक्षम नहीं थी। मामले पर मुकदमा चलाने और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान जीवित रहने के लिए, जो आकस्मिकता तब मौजूद नहीं रहेगी जब कार्यवाही निष्कर्ष के चरण तक पहुंच गई हो, हालांकि अंतिम रूप से समाप्त नहीं हुई हो।

मुझे नहीं लगता कि ऐसे आधार पर आवेदक को अंतरिम भरण-पोषण और मुकदमेबाजी के खर्च से इनकार किया जा सकता है, जब आवेदन मुख्य कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान दायर किया गया था और यह अदालत ही है जिसने उस पर अपने फैसले में देरी की। . यदि उपरोक्त स्थिति में राहत से इनकार नहीं किया जा सकता है तो निश्चित रूप से मुख्य याचिका के समापन के बाद भी आवेदक को उसी राहत से इनकार नहीं किया जाएगा।"

सुदर्शन कुमार खुराना बनाम श्रीमती मामले में इस निर्णय का पालन किया गया। दीपक (2) एवं भंवर लाल बनाम श्रीमती। कमला देवी (3). गोकल चंद मित्तल, जे. ने सुदर्शन कुमार खुराना के मामले (सुप्रा) में देखा कि धारा 24 और 26 को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

(1) ए.आई.आर. 1979 पी.बी. एवं हरियाणा, 211.

(2) ए.आई.आर. 1981 पी.बी. एवं हरियाणा 305.

(3) ए.आई.आर. 1983, राजस्थान, 229. z

पत्नी और बच्चे के लिए पेंडेंट लाइट। आम तौर पर, इन धाराओं के तहत याचिकाओं पर पहले निर्णय लिया जाता है और वास्तव में मुख्य याचिका के निष्कर्ष से पहले निर्णय लिया जाना चाहिए। आगे यह देखा गया है कि धारा 24 और 26 को पढ़ने से यह नहीं पता चलता है कि यदि धारा 9, 10, 12 या 13 के तहत मुख्य याचिका का निपटारा कर दिया जाता है, तो उसके बाद पारित होने वाले आदेश द्वारा भरण-पोषण पेंडेंट लाइट देने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। छीन लिया जाता है. भंवर लाल के मामले (सुप्रा) में इस दृष्टिकोण की पुष्टि की गई थी। एस. सुब्रमण्यम बनाम श्रीमती एम. जी. सरस्वती, (4) में मैसूर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया था। उसमें यह माना गया कि यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि कार्यवाही स्वयं समाप्त हो गई थी, इसलिए अंतरिम रखरखाव या व्यय

देने का कोई अवसर नहीं था। उन वस्तुओं का अधिकार, यदि स्थापित हो, तो समय बीतने और कार्यवाही की लंबितता समाप्त होने की अनुमति देकर पराजित नहीं किया जा सकता है। हम उपरोक्त मामलों में की गई टिप्पणियों से सम्मानजनक सहमत हैं।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निर्मला बनाम राम दास (5) का संदर्भ दिया; श्रीमती सावित्री पिपलानी बनाम सुभाष चंदर (6), श्रीमती। सवित्री पिपलानी बनाम सुभाष चंदर (7), रिपोर्ट, श्रीमती। चित्रा लेखा बनाम रंजीत राय। (8), और रीटा मागो बनाम वी. पी. मागो, (9)।

(7) निर्मला देवी के मामले (सुप्रा) में, पत्नी ने 14 जनवरी, 1970 को धारा 24 के तहत आरोप तय किया था, और धारा 24 के तहत आवेदन पर निर्णय किए बिना, मुख्य धारा 19 फरवरी, 1970 को न्यायालय द्वारा तय कर दी गई थी। धारा 24 के तहत आवेदन को खारिज करने के खिलाफ इस न्यायालय में अपील दायर की गई थी, विद्वान न्यायाधीश, निर्णय की प्रकृति से प्रतीत होता है, का विचार था कि धारा 24 के तहत आवेदन, मुख्य याचिका के निर्णय के कारण, नहीं दिया जा सका.

(8) 1979 के सिविल रिवीजन नंबर 114 (सुप्रा) में, ट्रायल कोर्ट ने, पत्नी के एक आवेदन पर, उसे रुपये की राशि दी। बच्चों और उसके लिए भरण-पोषण भत्ते के रूप में प्रति माह 50 रु. वह इस आधार पर आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण में आई कि

(4) ए.एल.आर. 1964 मैसूर 38.

(5) ए.आई.आर. 1973 पी.बी. एवं हरियाणा 48.

(6) सी.आर. 114 सन् 1979 का निर्णय 15 नवम्बर 1979 को हुआ।

(7) सी.आर. 244/80, 21 नवंबर 1980 को निर्णय लिया गया।

(8) ए.आई.आर. 1977, दिल्ली, 176.

(9) 1982 विवाह कानून रिपोर्ट 201 (दिल्ली)।

रखरखाव की राशि कम थी. पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान अंततः मुख्य याचिका का निस्तारण कर दिया गया। विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि याचिका निरर्थक हो गई है। ऐसी ही परिस्थितियों में. श्रीमती ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें रु. दिए जाने के आदेश के खिलाफ सावित्री पिपलानी फिर से पुनरीक्षण (सिविल रिवीजन नंबर 244/1980) में आईं। 75 प्रति माह भरण-पोषण पेंडेंट के रूप में, लेकिन उसे कार्यवाही का खर्च देने से इनकार कर दिया। पुनः, पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान, मुख्य याचिका का निस्तारण ट्रायल कोर्ट द्वारा कर दिया गया। विद्वान न्यायाधीश ने 1979 के सी.आर. संख्या 114 में अपनाए गए दृष्टिकोण

का पालन करते हुए पाया कि मुख्य मामले में कार्यवाही समाप्त होने के बाद ऐसे आदेशों की सत्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं थी। नतीजतन, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।

(9) विद्वान न्यायाधीशों का बहुत सम्मान करते हुए, हम उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार को स्वीकार करने में असमर्थ हैं: परिणामस्वरूप, हम इन तीनों मामलों को खारिज कर देते हैं।

(10) श्रीमती में। चित्रा लेखा के मामले (सुप्रा) में पति द्वारा न्यायिक अलगाव के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10(1) (बी) के तहत याचिका दायर की गई थी। पत्नी ने अंतरिम गुजारा भत्ता और मुकदमेबाजी खर्च देने के लिए धारा 24 के तहत आवेदन किया। धारा 24 के तहत आवेदन के निस्तारण से पहले पति की याचिका डिफॉल्ट के कारण खारिज कर दी गई। नतीजतन, धारा 24 के तहत आवेदन भी खारिज कर दिया गया। धारा 24 के तहत आदेश के खिलाफ अपील यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि कार्यवाही समाप्त होने के बाद कोई अंतरिम गुजारा भत्ता और मुकदमेबाजी खर्च नहीं दिया जा सकता है। रीटा मागो के मामले (सुप्रा) में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था। विद्वान न्यायाधीशों के प्रति अत्यधिक सम्मान के बावजूद, हम स्वयं को उस दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं कर पाए हैं।

(11) निर्धारण के लिए दूसरा प्रश्न यह उठता है कि यदि धारा 24 के तहत आवेदन मुख्य याचिका खारिज होने के बाद भी जारी रहता है, तो क्या आवेदक मुख्य याचिका के निर्णय या आवेदन के निस्तारण की तिथि तक भरण-पोषण का हकदार है? धारा 24 के तहत। धारा 24 को पहले ही ऊपर पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है। अनुभाग में "कार्यवाही" शब्द तीन स्थानों पर दिखाई देता है और यह मुख्य कार्यवाही को दर्शाता है, अर्थात, धारा 24 एफ के तहत कार्यवाही के अलावा अन्य कार्यवाही, शब्द "कार्यवाही के दौरान मासिक ऐसी राशि? बहुत महत्वपूर्ण हैं. ये शब्द विधायिका की मंशा को दर्शाते हैं कि उसका उद्देश्य मुख्य याचिका के निपटारे तक निर्धन पति या पत्नी को भरण-पोषण देना था। यदि अनुभाग के अंतर्गत आवेदन. 24 को शामिल करने के लिए लिया गया है-

"आगे बढ़ना" शब्द में, असंगत परिणाम आएंगे। इसलिए, हमारी राय है कि यदि धारा 24 के तहत आवेदन मुख्य याचिका खारिज होने के बाद भी जारी रहता है, तो आवेदक मुख्य याचिका के निर्णय की तारीख तक भरण-पोषण का हकदार है। सुदर्शन कुमार खुराना के मामले (सुप्रा) में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक अलग दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है, जिसमें यह देखा गया कि मुख्य याचिका के निष्कर्ष से परे भी धाराओं के तहत कार्यवाही तक पत्नी को भरण-पोषण लंबित याचिका नहीं देने का कोई औचित्य नहीं था। अधिनियम के 24 और 26

को अंतिम रूप दिया गया। विद्वान न्यायाधीश का अत्यंत सम्मान करते हुए, हम उपरोक्त टिप्पणियों से सहमत नहीं हैं। नतीजतन, हम उक्त मामले को केवल इस सीमा तक खारिज करते हैं। हालाँकि, यह दोहराया जा सकता है कि हमने इस मामले में विद्वान न्यायाधीश की अन्य टिप्पणियों को मंजूरी दे दी है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

(12) उपरोक्त कारणों से, हम पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे लागत सहित खारिज कर देते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा